संपादकीय जागरण

गुरुवार, 25 जनवरी, 2018 : माघ शुक्ल 8 वि. 2074

चुनौतियों में अवसर भी विद्यमान होता है

महाभियोग का शोशा

यह अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की माकपा नेता सीताराम येचुरी की सनसनीखेज पहल से खुद को दूर रखने के संकेत दिए। जब सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश के बीच मतभेद के मूल कारण अभी तक स्पष्ट नहीं और दोनों पक्ष अपने स्तर पर मामला सुलझाने की बात कर रहे हैं तब किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह ठीक नहीं कि वह न्यायाधीशों के विवाद में कूदे। यह सही है कि प्रेस कांफ्रेंस करने वाले सुप्रीम कोर्ट के चारों न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के तौर-तरीकों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि एक तो खुद उन्होंने सारी बातें सार्वजनिक करने से इन्कार किया और दूसरे, उनमें से एक न्यायाधीश ने साफ तौर पर यह कहा है कि अन्य किसी को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। एक तथ्य यह भी है कि चारों न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश के बीच मतभेद के कारणों की तह तक पहुंचे बिना इस नतीजे पर पहुंचना कठिन है कि कौन पक्ष कितना सही है? आखिर इन हालात में मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की जरूरत जताकर सीताराम येचुरी स्वयंभू न्यायाधीश बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह किस आधार पर इस नतीजे पर पहुंच गए कि जजों के विवाद में सारा दोष मुख्य न्यायाधीश का है और वह भी इस हद तक कि उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है? एक ऐसे समय जब चार न्यायाधीशों की ओर से प्रेस कांफ्रेंस करने से सुप्रीम कोर्ट की साख पहले से ही सवालों के घेरे में है तब मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाने की कोशिश इस संस्था की साख को और गिराने का ही काम करेगी।

संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने के बावजूद सीताराम येचुरी ने जिस तरह महाभियोग का शोशा उछाला उसके पीछे छुद्र राजनीति इसलिए भी दिख रही है, क्योंकि सभी को पता है कि प्रेस कांफ्रेंस की अगुआई करने वाले न्यायाधीश से मुलाकात करने का उतावलापन भाकपा सांसद डी राजा ने दिखाया था। क्या यह महज एक दुर्योग है कि भाकपा नेता प्रेस कांफ्रेंस करके देश को अवाक करने वाले न्यायाधीश से मुलाकात करना जरूरी समझते हैं और माकपा नेता मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना? कहीं येचुरी प्रकाश करात को चुनौती देने के लिए तो यह सब नहीं कर रहे हैं? वामपंथी नेताओं को इतनी राजनीतिक समझ होनी ही चाहिए कि मौजूदा स्थिति में सत्तापक्ष की सहमति के बिना किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का कोई मतलब नहीं। ऐसा महाभियोग प्रस्ताव तो केवल सुप्रीम कोर्ट की किरकिरी ही कराएगा जिसको पेश किए जाने के आधार ही पुष्ट न हों। कहीं ऐसा तो नहीं कि वामपंथी नेताओं का इरादा संकट से घिरे सुप्रीम कोर्ट की साख को खत्म करना है? यह सवाल इसलिए, क्योंकि वामपंथी दल संस्थाओं को नष्ट-भ्रष्ट करने के लिए ही अधिक जाने जाते हैं। अच्छा होगा कि वामपंथी दल और अन्य विपक्षी दल न्यायाधीशों के बीच के विवाद को राजनीतिक रोटियां सेंकने का जरिया न बनाएं।

सूखे से निपटने का तंत्र

सूखे की स्थिति पर नजर रखने के लिए योगी सरकार ने राज्य सूखा निगरानी केंद्र की स्थापना की है। किसानों के हित के लिए बनाया गया यह एक नया तंत्र है। इसे केंद्र सरकार के सूखा मैनुअल, 2016 में प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार स्थापित किया गया है। उद्देश्य है सूखे से संबंधित विभिन्न सूचकांकों जैसे कि वर्षा, भूमि उपयोग, कृषिजन्य दशाएं, भूगर्भ व सतही जल स्तर आदि के बारे में डाटाबेस तैयार करना। राज्य सूखा निगरानी केंद्र साथ ही सूखे से जुड़ी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों जैसे कि प्रवास और आपात स्थिति में संपत्ति बेचने आदि के बारे में आंकड़े इकट्ठे करेगा। इन विश्लेषणों से सूखे की स्थितियों का आकलन किया जाएगा। वर्षा, कृषि गतिविधियां, फसलों की दशा, चारा, जलाशय स्तर और पेयजल से संबंधित रिपोर्ट के आधार पर समय-समय पर सूखे के बारे में यह रिपोर्ट तैयार करेगा। इस पर सूखे से हुई क्षति के आकलन की जिम्मेदारी भी होगी। सूखे के संदर्भ में जल और मृदा प्रबंधन के साथ यह केंद्र व राज्य सरकार को सूखे की घोषणा के बारे में रिपोर्ट भी देगा।

> सूखा निगरानी केंद्र से प्राप्त आंकड़ों से आम लोगों खासकर किसानों को लाभ होता है तो निःसंदेह यह सराहनीय है

किसान हित के दावे के साथ सूखा निगरानी केंद्र की स्थापना की घोषणा काफी अहम है। सूचना क्रांति व तकनीक आधारितयुग में ऐसी किसी भी योजना का स्वागत किया जाना चाहिए जिससे अंतिम पंक्ति के लोग भी लाभान्वित होते हों। सूखा निगरानी केंद्र से प्राप्त आंकड़ों से आम लोगों खासकर किसानों को लाभ होता है तो निःसंदेह यह सराहनीय है, लेकिन यदि यह अन्य सरकारी इकाइयों की तरह शुष्क आंकड़े जमा करने और उबाऊ रिपोर्ट तैयार करने की एजेंसी बन गया तो इसकी उपयोगिता नहीं रह जायेगी।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

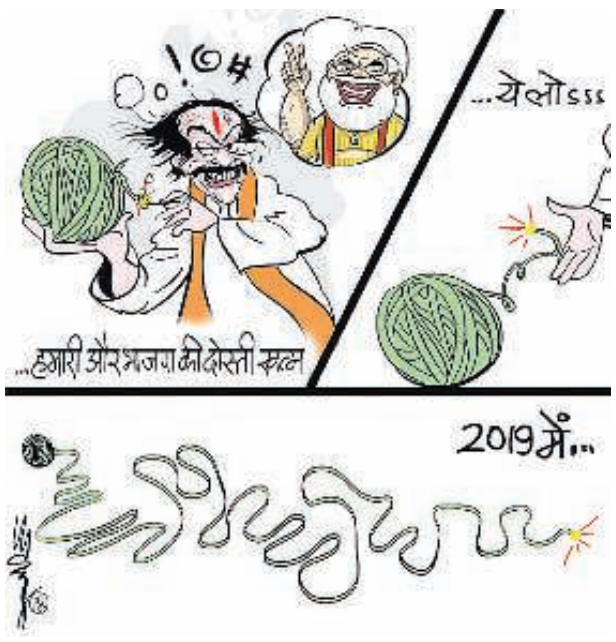

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या शिवसेना के अलग चुनाव लड़ने से भाजपा को नुकसान होगा?

आज का सवाल
क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेता के रूप में उभर रहे हैं?

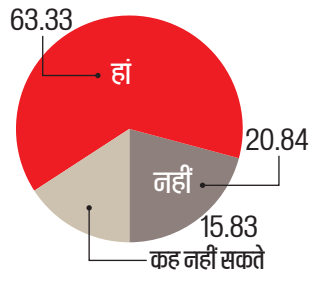

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम एसएमएस से प्राप्त नतीजों के साथ जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

भारत-आसियान दोस्ती का नया दौर

ली सीन लूंग

भारत-आसियान की जुगलबंदी से ऐसे एकीकृत एशियाई बाजार का निर्माण होगा जिसमें दुनिया की करीब एक तिहाई जीडीपी शामिल होगी

भारत-आसियान रिश्तों की रजत जयंती मनाने की तैयारी के बीच हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के रिश्ते दो हजार वर्षों से भी अधिक पुराने हैं। इतिहास में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि प्राचीन भारत और कंबोडिया, मलेशिया और थाईलैंड के बीच व्यापार हुआ करता था। इन प्राचीन संपर्कों ने दक्षिणपूर्व एशियाई संस्कृति, परंपराओं और भाषाओं को प्रभावित किया। सभी जगहों पर भारतीय हिंदू-बौद्ध प्रभाव की छाप साफ तौर पर नजर आती है। इंडोनेशिया, म्यांमार और थाईलैंड सहित कई दक्षिणपूर्व एशियाई देशों में रामायण को खासा महत्व दिया जाता है। सिंगापुर के मलय नाम की उत्पत्ति भी संस्कृत भाषा से ही हुई है जिसका अर्थ होता है लॉयन सिटी यानी सिंह का शहर। सिंगापुर हमेशा से ही आसियान में भारत के प्रवेश का समर्थक रहा है। भारत 1992 में आसियान की एक श्रेणी में संवाद साझेदार बना और 1995 में पूर्ण रूप से संवाद साझेदार। उसने 2005 से सभी पूर्वी एशिया सम्मेलनों में भाग लिया। पूर्वी एशिया सम्मेलन इस क्षेत्र के प्रमुख नेताओं के नेतृत्व वाला एक खुला, समावेशी और तेजी से बढ़ता क्षेत्रीय मंच है।

समय के साथ भारत-आसियान रिश्ते और परवान चढ़ते गए और 2012 में दोस्ती की बीसवीं वर्षगांठ के अवसर पर रणनीतिक साझेदारी में बदल गए। दोनों पक्ष आज आसियान के विभिन्न राजनीतिक-सुरक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट नीति में भी व्यापार, संपर्क और संस्कृति की तिकड़ी पर जोर दिया गया है। इस मंत्र के माध्यम से वह आसियान के साथ सक्रियता को और धार देना चाहते हैं जो हमारे बहुस्तरीय और व्यापक सहयोग को दर्शाता है। हमारे पास सहयोग के लिए लगभग 30 प्लेटफॉर्म हैं। समय के साथ दोनों पक्षों के बीच व्यापार में भी बहुत तेजी आई है। इसमें आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी एआइएफटीए जैसे समझौते की अहम भूमिका रही है। आसियान-भारत व्यापार 1993 के 2.9 अरब डॉलर से उछलकर 2016 में 58.4 अरब डॉलर हो गया। सामाजिक सांस्कृतिक मोर्चे पर भी आसियान-भारत छात्र विनिमय कार्यक्रम और दिल्ली डायलॉग ने दोनों पक्षों के बीच जनसंपर्क को और तेजी दी है। इन मंचों के माध्यम से हमारे युवा, अकादमिक और कारोबारी जगत के लोगों को एक दूसरे से मुलाकात के दौरान सीखने-समझने का अवसर मिला है जिससे रिश्ते और मजबूत हुए हैं।

भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान की भागीदारी से दोनों पक्षों की उत्सवधर्मिता चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रण आसियान नेताओं के लिए बहुत सम्मान की बात है। वैश्विक स्तर पर पल-प्रतिपल बदल रही परिस्थितियों में चुनौतियों के साथ अवसर भी विद्यमान हैं। रणनीतिक संतुलन की धुरी खिसक रही है। दुनिया के कई हिस्सों में जनसांख्यिकीय और राजनीतिक स्तर पर बदलाव आकार ले रहे हैं। वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार पर सहमति जरूर प्रभावित हुई है, लेकिन एशिया में यह सकारात्मक बनी हुई है। हमें आर्थिक जुड़ाव की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। साथ ही आतंकवाद, साइबर अपराध और जलवायु परिवर्तन जैसी उभरती चुनौतियों से निपटने को लेकर भी सतर्क रहना होगा।

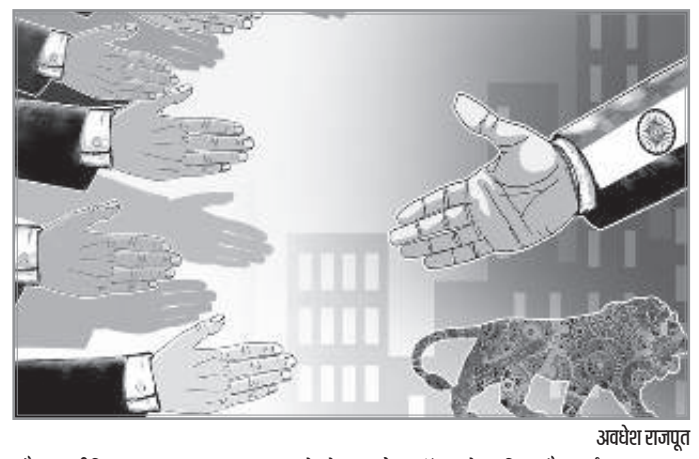

अवधेश राजपूत

कई अहम पैमानों पर भारत और आसियान की सोच भी एकसमान है। क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के साथ ही खुली, संतुलित और समावेशी अवधारणा पर भी दोनों एकमत हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच कई प्रमुख समुद्री मार्गों के बीच स्थित है। ये समुद्री मार्ग तमाम आसियान देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग भी हैं। ऐसे में व्यापार को सुगम बनाए रखने के लिए इन समुद्री मार्गों की सुरक्षा दोनों पक्षों के लिए समान रूप से आवश्यक है। आसियान और भारत की करीब 180 करोड़ की जनसंख्या है जो दुनिया की एक चौथाई आबादी के बराबर है। हमारा सम्मिलित जीडीपी भी 4.5 लाख करोड़ डॉलर से अधिक है। वर्ष 2025 तक भारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा तो दक्षिणपूर्व एशिया में भी मध्यवर्ग का दायरा भी दोगुना बढ़कर 16.3 करोड़ होने का अनुमान है। आसियान की 60 प्रतिशत से अधिक आबादी 35 साल से कम के युवाओं की है तो वर्ष 2020 तक 29 वर्ष की औसत आयु के साथ भारत दुनिया का सबसे युवा देश होगा। आसियान और भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की मांग भी तूफानी रफ्तार से बढ़ रही है जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से कुलांचे भर सकती है। दोनों पक्षों में इतनी अनुकूलता होने के बावजूद संबंधों को नया आयाम देने के लिए अभी भी बहुत गुंजाइश बाकी है। आसियान के विदेशी व्यापार में भारत की हिस्सेदारी महज 2.6 प्रतिशत है जिसे और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है।

परस्पर लाभ के लिए मैं तीन सुझाव देना चाहूंगा। पहला यह कि व्यापार और निवेश को और गति देने के लिए भारत और आसियान को दोगुनी गति से प्रयास करने चाहिए। हमें मुक्त व्यापार सहित मौजूदा रास्तों को समय रहते सुधार करने के साथ उन्हें प्रासंगिक बनाए रखना होगा। मौजूदा एआइएफटीए से भी बढ़कर उच्च स्तरीय क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी आरसीईपी जैसी पहल की ओर कदम बढ़ाने होंगे। इससे ऐसे एकीकृत एशियाई बाजार का निर्माण होगा जिसमें दुनिया की लगभग एक तिहाई जीडीपी शामिल होगी। दोनों ओर से नियम-कानूनों को सुसंगत बनाना होगा और भारत की एक्ट ईस्ट नीति को सफल बनाने के साथ ही क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाने के मकसद से मेक इन इंडिया को भी हरसंभव सहयोग देना होगा। दूसरा सुझाव यह है कि जल, थल और वायु परिवहन के मोर्चे पर सुधार हो। इस दिशा में भारत के प्रयास सराहनीय है जहां वह भारत-म्यांमार-थाईलैंड हाईवे के विस्तार के साथ ही आसियान के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी ढांचा विकास हेतु एक अरब डॉलर की राशि के लिए सहमत हुआ है। तीसरा सुझाव डिजिटल कनेक्टिविटी सहयोग का है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत में आधार से जुड़ा तंत्र नए अवसर तैयार कर रहा है।

आसियान का अध्यक्ष होने के नाते सिंगापुर का एक लक्ष्य आसियान स्मार्ट सिटी नेटवर्क तैयार करना भी है जिसमें भारत हमारा स्वाभाविक साझेदार है। भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। उसने 100 स्मार्ट सिटी विकसित करने का लक्ष्य भी तय किया है। एक शहरी-राष्ट्र होने के नाते हम अपने अनुभव से इसमें भारत की पूरी मदद करेंगे। आंध्र प्रदेश की नई विकसित हो रही राजधानी अमरावती इसका एक उदाहरण है। आसियान का अध्यक्ष होने के नाते सिंगापुर भारत के साथ रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर दोनों पक्ष अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव से मौजूदा चुनौतियों का समाधान निकालकर भविष्य के लिए बेहतर बुनियाद रखते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां ही इससे सबसे अधिक लाभान्वित होंगी।

(लेखक सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं)

response@jagran.com

कहे हुए को करके दिखाने की चुनौती

प्रदीप सिंह

प्रधानमंत्री ने विश्व आर्थिक मंच से जो कहा उसे लागू करने की चुनौती वैश्विक स्तर पर ही नहीं घरेलू मोर्चे पर भी है

क्या वैश्विक मंच पर एक अहम भूमिका निभाने का भारत का समय आ गया है? वैश्विक व्यवस्था में भारत अपना जायज स्थान हासिल करने के लिए तैयार है। ऐसा दावा भारत का कोई नेता नहीं भारत, पाकिस्तान और दक्षिण एशिया मामलों की जानकार एलिसा आयरस की नई किताब में किया गया है। किताब का शीर्षक ही है- अवर टाइम हैज कमः हाऊ इंडिया इज मेकिंग इट्स प्लेस इन द वर्ल्ड। मंगलवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण ही नहीं उसके प्रति विश्व समुदाय की उत्सुकता, उसे मिली सराहना और समर्थन इसकी पुष्टि करता है। प्रधानमंत्री को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। ऐसा करने वाले दुनिया के उद्योग जगत और सरकारों के बड़े लोग थे। यह देश के बढ़ते रुतबे का प्रमाण है। आज दुनिया भारत और मोदी की ओर उम्मीद की नजर से देख रही है। इसलिए देश और प्रधानमंत्री के लिए यह अवसर भी है और चुनौती भी। एलिसा किताब में इस उदीयमान गणतंत्र के महाशक्ति बनने के रास्ते की रुकावटों और इसका अमेरिका और दूसरे बड़े देशों पर पड़ने वाले प्रभाव की भी चर्चा करती हैं। उनके मुताबिक पिछली एक चौथाई शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार ने उसे उभरती महाशक्ति बना दिया है। मजबूत अर्थव्यवस्था और बड़ी सैन्य शक्ति के आधार पर भारत अब वैश्विक व्यवस्था में अपनी जगह चाहता है। भारत यह जगह किसी को हटाकर नहीं, अपनी शक्ति और योग्यता के आधार पर हासिल करना चाहता है। भारत सभी मामलों में फिर चाहे वह रक्षा हो, व्यापार या जलवायु परिवर्तन का मुद्दा, अपनी शर्तों पर समझौते करना चाहता है।

दावोस में प्रधानमंत्री ने तीन मुद्दों संरक्षणवाद, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद को दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में पेश किया। संरक्षणवाद पर हमला करके उन्होंने एक तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बिना उनकी 'अमेरिका फर्स्ट' की नीति की आलोचना की। सम्मेलन में दुनिया की सौ बड़ी कंपनियों के सीईओ भी मौजूद थे। वे मोदी से यही सुनना चाहते थे। पिछले साल इसी सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग भी संरक्षणवाद के खिलाफ और भूमंडलीकरण के पक्ष में बोले थे, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री ने संरक्षणवाद को आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक बताया। नरेंद्र मोदी ने पिछले साढ़े तीन साल में विदेश नीति और भारत की साख को एक नई ऊंचाई दी है। बीस साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री विश्व आर्थिक फोरम के मंच पर गया, पर उस समय की दुनिया ही नहीं भारत भी अब वह भारत नहीं रहा।

2025 तक देश की अर्थव्यवस्था का आकार आज से लगभग दोगुना यानी पांच ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। प्रधानमंत्री के दावोस पहुंचने वाले दिन ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से एक अच्छी खबर आई कि 2018 में भारत की विकास दर सात दशमलव चार फीसदी होगी और वह दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था होगी। इस सबके बावजूद दावोस में जो चमक-दमक दिख रही थी वह दरअसल देश और दुनिया की पूरी हकीकत नहीं है। देश और दुनिया में अभी भूख, गरीबी, अभाव और असमानता व्याप्त है। भारत को भारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जरूरत है। सरकार विदेशी निवेश के लिए लाल कालीन भी बिछा रही है। आर्थिक सुधारों की गति भी तेज की गई है।

प्रधानमंत्री ने विश्व के सबसे बड़े आर्थिक मंच से जो कहा उसे अब लागू करने की चुनौती है। यह चुनौती वैश्विक स्तर पर ही नहीं घरेलू मोर्चे पर भी है। यह सही है कि पिछले कुछ सालों से दुनिया में भूमंडलीकरण के खिलाफ जनमानस बन रहा है। आर्थिक संरक्षणवाद और राष्ट्रीयता जनादेश का आधार बन रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से निकलना, इटली और जर्मनी के चुनाव और यहां तक कि खुद नरेंद्र मोदी की 2014 में जीत इस बात का संकेत है कि दुनिया के बड़े जनतांत्रिक देशों का जनमानस भूमंडलीकरण से हुए नुकसान के कारण अब संरक्षणवाद की ओर लौटना चाहता है। ऐसे में भारत और चीन जैसे देशों के लिए भूमंडलीकरण को बढ़ाने की कोशिश (हालांकि दोनों के कारण अलग-अलग हैं) आसान काम नहीं है। दुनिया के अन्य देशों के सामने चुनौती है कि भूमंडलीकरण को समावेशी विकास से जोड़ने का प्रयास करें। मंगलवार को ही एक और खबर आई जिसके मुतबिक भारत की 73 फीसदी संपत्ति सिर्फ एक फीसदी लोगों के पास है। वैश्विक स्तर पर भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ती खाई को पाटने या कम करने की चुनौती पूरी दुनिया के लिए समस्या है। भारत के लिए यह और बड़ी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सारा जोर समाज के पिछड़े और कमजोर तबके की ओर है। विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोलने का मतलब यह है कि हमें अपना बाजार भी खोलना पड़ेगा। ऐसे में देशी उद्योगों को संरक्षण कैसे मिलेगा? दोनों को साधना पतली रस्सी पर चलने जैसा है। दावोस में प्रधानमंत्री मोदी को लोगों ने ध्यान से सुना तो इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी रही कि उन्हें भारत में विकास और समृद्धि की अपार संभावनाएं नजर आती हैं, जो उनके लिए निवेश और व्यापार के अवसर उपलब्ध कराती है। इस नाते प्रधानमंत्री के सामने और बड़ी चुनौती है, अपने इरादों और नीतियों को सही ढंग से सही समय पर लागू करने की। इस मामले में मोदी सरकार की पहली परीक्षा आगामी बजट होने जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने दावोस में बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) की बैठक में कहा भी कि देखना है कि बजट के बाद आप लोग मुझे कितना पसंद करते हैं? आम बजट प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री अरुण जेटली के लिए विदेशी और घरेलू निवेशकों के लिए स्पष्ट संदेश की निरंतरता की भी परीक्षा है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले यह आखिरी बजट होगा इसलिए सरकार की नजर अपने वोट बैंक पर भी होगी। प्रधानमंत्री दावोस रवाना होने से पहले एक साक्षात्कार में कह चुके हैं कि लोक-लुभावन घोषणाओं की राजनीति में उनका यकीन नहीं है। प्रतिस्पर्धी चुनावी राजनीति में इस तरह की नीति प्रधानमंत्री की पार्टी के लिए खतरा भी बन सकती है। अभी तक मोदी ने अपने फैसलों के प्रति अदम्य आत्मविश्वास दिखाया है। देश के मतदाताओं ने भी उनके भरोसे को तोड़ा नहीं है। नोटबंदी और जीएसटी लागू करने में आई तमाम समस्याओं के बावजूद लोगों का विश्वास मोदी से डिगा नहीं है। सवाल यही है कि क्या 2019 तक यह भरोसा कायम रहेगा?

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

जनहित

इंसान समाज में रहता है। इसलिए समाज ने उसके कुछ दायित्व भी तय किए हैं। हालांकि समाज हमसे कोई विशेष कार्य की मांग नहीं करता, बल्कि जो कुछ हमें समाज से प्राप्त होता है, उसे ही हमें किसी न किसी रूप में समाज को वापस करना होता है। मनुष्य को कभी भी यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसका अस्तित्व समाज से है, समाज का अस्तित्व उससे नहीं। जो मनुष्य समाज से अलग-थलग होकर चलते हैं, उन्हें जीवनभर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जबकि जो व्यक्ति समाज के साथ मिलकर चलते हैं, उनकी बड़ी से बड़ी समस्या तक मिनटों में हल हो जाती है। इसका कारण यही है कि सामाजिक होने के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति हमारी समस्या या चिंता का निदान खोजने की कोशिश करता है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर जनहित और लोक-कल्याण के बारे में सोचे। जब हम दूसरों के बारे में सोचकर कर्म करते हैं तो हमें इसका दोहरा लाभ मिलता है। हमें आत्म-संतुष्टि का अहसास होता है, जबकि ऐसा करके हम अपने भविष्य के कष्टों को भी काटते या उनका प्रभाव कम करते हैं।

हमारे जनहित के कार्य से जितने भी लोग प्रभावित-लाभान्वित होते हैं, वे बदले में हमें प्यार, स्नेह, आशीर्वाद और दुआ देते हैं, जिससे हमारे कष्ट अप्रभावी हो जाते हैं या फिर हममें उन्हें सहने की असीम ताकत आ जाती है। इसी तरह यदि हमसे भूतकाल में जाने-अनजाने कोई पाप या गलत कार्य हो गया हो तो भी जनहित से जुड़े कार्य करके मनुष्य पश्चाताप या मुक्ति प्राप्त कर सकता है। धर्म-शास्त्रों में कहा गया है कि यदि किसी मनुष्य ने अपने जीवन का तीन चौथाई हिस्सा गलत कार्यों में खर्च कर दिया है तो भी वह शेष बचे समय में सद्कर्म या जनहित के कार्य करके पश्चाताप कर सकता है। अर्थात अंत भला तो सब भला। जनहित के कार्य करने के लिए मनुष्य को केवल एक छोटा-सा प्रयास करना होता है। दुख-दर्द सभी के जीवन में हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने दुखों को ही सबसे बड़ा और जटिल मान लेता है, उससे जनहित के कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके विपरीत जो दूसरों के दुखों को महसूस करे और उनके सामने अपने दुख को भूल जाए, वास्तव में वही जनहित के बारे में सोच सकता है।

आचार्य अनिल वत्स

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

सरकारी उदासीनता की मार झेलती शिक्षा

दयनीय दशा से दो-चार शिक्षा शीर्षक से लिखे अपने लेख में मृणाल पाण्डे ने शोध रपट 'असर' के ताजा आंकड़ों का हवाला देते हुए ग्रामीण शिक्षा के गिरते स्तर को उजागर किया है। एक तरफ सरकार ग्रामीण युवाओं को शिक्षित कर स्वावलंबी बनाने के लिए सर्वशिक्षा अभियान की वकालत कर रही है। वहीं दूसरी तरफ संसाधनों के अभाव में ग्रामीण शिक्षा के निरंतर गिरते स्तर को नजरअंदाज कर उसे सिर्फ वोट बैंक के नजरिये से ही देख रही है। देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम केवल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ही नहीं, बल्कि गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भी लागू किया गया है, लेकिन आंकड़े यही बयां करते हैं कि शहरी शिक्षा की तुलना में ग्रामीण शिक्षा बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। आज भी ग्रामीण सरकारी स्कूलों में शहरों की तुलना में संसाधनों का भारी अभाव बना हुआ है। वे आज की प्रचलित तकनीकी से भी कोसों दूर हैं। एक सबसे बड़ी कमी सुशिक्षित अध्यापकों की है। इसी का नतीजा है कि आज हमारे ग्रामीण युवा अंग्रेजी तो दूर अपनी मातृभाषा भी पढ़ने में असमर्थ हैं। ऐसे बच्चों से देश के तकनीकी विकास व स्वयं के लिए रोजगार जुटाने की उम्मीद करना बेईमानी होगी। इन सबके पीछे सिर्फ सरकार का ही हाथ है। जिसने वोट बैंक की नीति के फलस्वरूप केवल मुफ्तखोरी को ही बढ़ावा दिया है। कभी साइकिल तो कभी लैपटॉप और मिड-डे मील योजना ने तो ग्रामीण सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को अधिक लचर बनाया है जिसके कारण बच्चों का ध्यान पढ़ाई की ओर कम खाने की ओर ज्यादा रहता है। मिड-डे मील योजना लागू करके सरकार ने शिक्षालयों को केवल भोजनालयों में तब्दील करने का ही दयनीय कार्य किया है। सरकारी महकमों से जुड़े सभी सच्जनों के बच्चे लगभग अच्छी व महंगी तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूलों से केवल गरीबों का ही नाता रहा है।

पिंटू सक्सेना, लखनऊ

आर्थिक असमानता

भारत में जिस तरह धनाढ्य लोगों के हाथों में संपत्ति का ग्राफ बढ़ रहा है उसके प्रति हमें जल्दी सचेत होने की जरूरत है। आकड़ों के अनुसार बीते साल भारत में पैदा हुई कुल संपत्ति का 73 प्रतिशत हिस्सा देश के एक फीसदी धनाढ्य लोगों के हाथों में है। इतनी तेज बढ़ती असमानता देश के सामाजिक ढांचे को बिगाड़ सकती है। सरकार और समाज को समय रहते सचेत होने की जरूरत है, वरना इसके नतीजे घातक हो सकते हैं।

ss6066356@gmail.com

विवाद का हल

फिल्म पदमावत व दिल्ली में सीलिंग का विरोध जोरों पर है। इससे सड़क जाम, तोड़फोड़ और आगजनी आदि हो रही है। विरोध का यह तरीका उचित नहीं है। इसके लिए शांतिपूर्वक संवाद, सभा, अनशन और प्रदर्शन आदि हो सकता है जिसमें किसी को हानि न हो। सरकार भी आग लगने के बाद ही कुआं खोदने की बात सोचती है। समय रहते ऐसे मामलों का हल निकाल लेना चाहिए।

वेद मामूरपुर, नरेला

जिद अच्छी नहीं

संजय लीला भंसाली की फिल्म पदमावत को कोर्ट ने हरी झंडी दिखाकर गेंद राज्यों के पाले में डाल दी है। फिल्म को लेकर अभी संशय खत्म नहीं हुआ है। 25 जनवरी को रिलीज होने वाली ये फिल्म कहीं करणी सेना के आक्रोश का शिकार होकर राज्यों का सिरदर्द ना बन जाए। लगता है ये फिल्म सबके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है जो कि ठीक नही है। जिद अच्छी होती है पर हर जिद अच्छी नही होती।

mahesh_nenava@yahoo.com

बहन-बेटियों की सुरक्षा

हम देश -विदेश में मानवतावादी और प्रगतिवादी होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन देश में बेटियों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में कई बेटियों की इज्जत तार-तार हो चुकी है। ऐसी घटनाएं अन्य प्रदेशों में भी हो रही हैं। इन घटनाओं से सामाजिक शर्मिंदगी महसूस की जा रही है। हरियाणा से ही बेटी बचाओ -बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई थी, इस तरह के सबसे ज्यादा अपराध की खबरें हरियाणा से आ रही हैं। दुष्कर्म पीड़िता घुट -घुट कर जीने को विवश हो जाती है। उसका जीवन नारकीय बन जाता है। हम किस युग में जी रहे हैं? विकास से पहले सरकार को महिलाओं और युवतियों को सुरक्षा देनी होगी। युवतियों पर एसिड अटैक एक समाजिक त्रासदी बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसिड की खरीद- फरोख्त पर रोक लगाई थी, लेकिन आज भी बाजारों में खुलेआम मिलता दिख जाएगा। इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह सरकार ने दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना दोषियों को फांसी जैसी सजा मुकर्रर कर दी है। इस तरह की सजा का प्रावधान अन्य प्रदेशों में भी किया जाना चाहिए। लिंग अनुपात में एक हजार पुरुष पर 950 महिला होनी चाहिए, लेकिन अभी चौकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। महिला अनुपात में कमी के कारण विशेषकर हरियाणा के ही कई इलाकों में युवकों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। महिला सशक्तीकरण की दिशा में अवश्य प्रगति हुई है लेकिन महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध की घटनाएं चिंता का विषय है। जिस देश में बहन-बेटियों को सुरक्षा और सम्मान नहीं मिलता वह देश प्रगति नहीं कर सकता है। सरकारों को बेटियों को सुरक्षित माहौल देना होगा। इसके लिए सरकारों को सामाजिक शिक्षा और नैतिकता का पाठ पाठ्यपुस्तकों में पढ़ाना चाहिए।

kantilalmandot@gmail.com

ट्वीट-ट्वीट

गुरुग्राम में हुई हिंसा यह बताती है कि किस तरह कुछ संगठन संस्कृति और सम्मान की आड़ में कानून के शासन और लोकतंत्र को बंधक बनाते हैं।

कार्तिकेय शर्मा@kartikeya_1975

पद्मावत के खिलाफ हिंसा के भय से गुरुग्राम में पब और क्लब भी बंद रहेंगे। यह कहां आ गए हम? किस तरह का देश बन रहे हैं हम?

जक्का जैकब@Zakka_Jacob

हरियाणा में बच्चों से भरी स्कूल बस पर हमला। राजस्थान और गुजरात में बेलगाम भीड़ की हिंसा। खेद के साथ कहना पड़ रहा कि भाजपा सरकारें हुड़दंगियों पर ल